

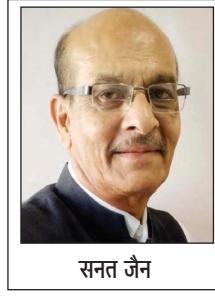


ललित गग्नी

जम्मू एवं कश्मीर के
चुनाव अनेक दृष्टियों से न
केवल राजनीतिक दशा-
दिशा स्पष्ट करेंगे बल्कि
बल्कि राज्य के उद्योग,
पर्यटन, रोजगार, व्यापार,
रक्षा, शांति आदि नीतियों
तथा राज्य की पूरी जीवन
शैली व भाईचारे की
संस्कृति को प्रभावित
करेगा। वैसे तो हर चुनाव
में वर्ग, जाति, सम्प्रदाय का
आधार रहता है, पर इस
बार वर्ग, जाति, धर्म,
सम्प्रदाय व क्षेत्रीयता
व्यापक रूप से उभर कर
सामने आयेगी। मतदाता
जहाँ ज्यादा जागरूक
दिखाई दे रहा है, वहीं
राजनीतिज्ञ भी ज्यादा
समझदार एवं चतुर बने हुए
दिख रहे हैं।

संपादकीय

यागों का नसाहत



मा रत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। विभिन्न उद्योग, मार्केटिंग, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन भविष्य में आने वाले हैं। लगभग 10 फीसदी इसका प्रभाव वर्तमान में देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोग की पहचान, दवाइयाँ और इलाज के संबंध में विस्तृत जानकारी, मरीज का देखरेख एआई के माध्यम से महत्वपूर्ण सेवाएँ जल्द शुरू होगी। एआई के माध्यम से टेली मैडिसिन, रिमोट सर्जरी के भी नए आयाम शुरू होंगे। इसमें डॉक्टर नस एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी हैं उसमें तकनीकि के माध्यम से बेहतर सेवाएँ दे सकेंगे। अभी जो कमी बनी हुई है उसे आसानी से पूरा किया जा सकेगा। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत बड़े परिवर्तन आने जा रहे हैं। एआई तकनीकि के माध्यम से फसल की उपज, मौसम की भविष्यवाणी, फसलों में लगने वाले कीट और उनका उपचार फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कृषि विज्ञान के छात्रों के पढ़ाई में इससे मदद मिलेगी। डेटा उपलब्धता और विविधता के कारण चैट वाट्स और वर्चुअल डिजिटल

चिंतन-मनन

साधना और सुविधा



इयन इकॉनमी: अ रिव्यू' रिपोर्ट, जिसे सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बजट पेश करने से पहले जारी किया था, में अर्थव्यवस्था के 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक भारत के विकासित देश बनने की बात कही गई है। सवाल का उठना लाजिम है कि क्या सचमुच यह मुम्किन है, क्योंकि अभी भी भारत विकासशील देश है, और कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करना, गरीबी का खात्मा, आधारभूत संरचना को और मजबूत बनाना, शिक्षा के स्तर में इजाफा, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ातरी, सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना आदि शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में नॉर्मिनल जीडीपी के 7 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही। रिपोर्ट में यह भी संभावना जारी रखी है कि भारत की जीडीपी

जम्मू-कश्मीर चुनाव से नये दौर की उम्मीद



क नाम था। यह आलम तब ह, जब पहला सूची भारतीय की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंजूर को गई थी। यदि भाजपा औरें से अलग तथा अनुशासित दल की अस्तित्व के प्रति सचेत है तो उसे प्रत्याशी चयन की अप्रक्रिया को लोकतांत्रिक आकार देना ही होगा। पहले उस सूची का विरोध जिन कारणों से हुआ, उनमें एक तो दूसरों से आए नेताओं को प्रत्याशी बनाना रहा और दूसरों दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्रियों का नाम न होना। लगता है भाजपा को अभी भी लोकसभा चुनावों में हुई गलतियों का आशंका नहीं है। लोकसभा चुनाव में उसे दूसरे दलों के नेताओं का चुनाव मैदान में उतारने का किस तरह नुकसान उठाना चाहिए। जमू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए जिस प्रत्याशियों की सूची का विरोध यह भी बताता है कि भाजपा प्रत्याशी चयन की कोई नीर-क्षीर, पारदर्शी और ऐसी प्रक्रिया का निर्माण नहीं कर सकता है, जिससे असंतोष, विरोध और भिट्ठरघात का सामना न करना पड़े। वैसे यह समस्या के भाजपा की ही नहीं, सभी दलों की है। कम से कम यहाँ होना ही चाहिए कि राजनीतिक दल प्रत्याशियों के चयन का अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की राय को महत्व दें। कठिन कार्य नहीं, लेकिन हमारे राजनीतिक दल आंतर्मिश्र लोकतंत्र विकसित करने से बच रहे हैं।

चुनाव अभियान प्रारम्भ हो रहा है। प्रत्याशियों के नामांकन हो रहे हैं। सब राजनीतिक दल अपने-अपने घाढ़ोषणा-प्रक्रिया को ही गीता का सार व नीम की पत्ती बताकर सब समस्त

मिटा दन तथा सब रागों का दवा बन जान का नातकता ५
बातें करते हुए व्यवहार में अनैतिकता को छिपायेंगे। टुकड़े
टुकड़े बिखरे कुछ दल फेवीकॉल लगाकर एक होंगे। सभी
तक पहुँचने के लिए कुछ दल परिवर्तन को आकर्षण
आवश्यकता बतायेंगे। इस बार दलों में जितना अन्दर-बाहर
होता हुआ दिख रहा है, उससे स्पष्ट है कि चुनाव परिणाम
के बाद भी एक बड़ा दौर असमंजस का चलेगा। ऐसी
स्थिति में मतदाता अगर बिना विवेक के अंख मूंदकर मृत्यु
देगा तो परिणाम उस उक्ति को चरितार्थ करेगा कि हाँ अब
अंधा अंधे को नेतृत्व देगा तो दोनों खाई में गिरेंगे हाँ इसलिए
प्रांत के लोगों को मतदान करते हुए विवेक का परिचय देना
होगा।

इन चुनावों की जटिलता का अंदाजा इस बात से भी लग
है कि एक दशक पहले यानी 2014 में हुए विधानसभा
चुनाव के समय अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे से लै
जम्पू-कश्मीर अब विशेष राज्य के दर्जे से भी वर्चित हैं।
उस चुनाव में दो सबसे बड़ी और मिलकर सरकार बनाने
वाली पार्टियां पीडीपी और भाजपा एक-दूसरे की धूर विरोध
हो चुकी हैं। राज्य में अब भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व
में हिन्दू बहुल सीटों और कश्मीरी पंडितों के बोट बैंक ट्रैक
अपने खाते में डालने के इरादे से मैदान में उतर रही है और
ऐसे में कंप्रेस की हालत खराब होना तय माना जा रहा है।
भले ही सभी क्षेत्रीय पार्टियां ने भाजपा के साथ गठबंधन
करने से इंकार कर दिया है, लेकिन भाजपा की मजबूती

स्थिति को देखते हुए भविष्य में क्षत्रीय दलों के भाजपा के साथ बहती हवा में जाने की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर एक राज्य के रूप में शुरू से विशिष्ट रहा है, इस दृष्टि से वहाँ होने वाले चुनाव भी विशेष एवं अन्य राज्यों से भिन्न है। बड़ी बात यह है कि पार्टीयां एक-दूसरे के बारे में चाहे जो भी कहें, ये सभी भारतीय संविधान के तहत लोकतात्रिक ढंग से चुनाव में हिस्सेदारी कर रही हैं और जनादेश को भी स्वीकार करेंगी। निश्चित ही इन चुनाव परिणामों से उम्मीद जगी है कि यहाँ से जम्मू-कश्मीर में लोकतात्रिक विकास और सांति-समृद्धि-स्थिता का नया दौर शुरू होगा। ऐसा होना ही इन चुनावों की सार्थकता है।

जम्मू एवं कश्मार के चुनाव अनक दृष्टिया से न कबल राजनीतिक दशा-दिशा स्पष्ट करेंगे बल्कि बल्कि राज्य के उद्योग, पर्यटन, रोजगार, व्यापार, रक्षा, शांति आदि नीतियों तथा राज्य की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। वैसे तो हर चुनाव में वर्ग, जाति, सम्प्रदाय का आधार रहता है, पर इस बार वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय व क्षेत्रीयता व्यापक रूप से उभर कर सामने आयेगी। मतदाता जहाँ ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहा है, वहाँ राजनीतिज्ञ भी ज्यादा समझदार एवं चतुर बने हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार चुनावी शतरंज पर काले-सफेद मोहरें रखे हैं, उससे मतदाता भी उलझा हुआ है। अपने हित की पात्रता नहीं मिल रही है। कौन ले जाएगा राज्य की एक करोड़ लाख पच्चीस लाख जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विकास एवं शांति की दिशा में? सभी नगे खड़े हैं, मतदाता किसको कपड़े पहनाएगा, यह एक दिन के राजा पर निर्भर करता है। चुनाव घोषित हो जाने से तथा प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से जो क्रियाएं-प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसने ही सबके दिमागों में सोच की एक तेजी ला दी है। प्रत्याशियों के चयन व मतदाताओं को रिझाने के कार्य में तेजी आती जायेगी। परम आवश्यक है कि सर्वप्रथम राज्य का वातावरण चुनावों के अनुकूल बने। राज्य ने सम्प्रदायिकता, आतंकवाद तथा अस्थिरता के जंगल में एक लम्बा सफर तय किया है। उसकी मानसिकता धायल है तथा जिस विश्वास के धरातल पर उसकी सोच ठहरी हुई थी, वह भी हिली है। पुराने चेहरों पर उसका विश्वास नहीं रहा। अब प्रत्याशियों का चयन कुछ उसूलों के आधार पर होना चाहिए न कि जाति और जीतने की निश्चितता के आधार पर। मतदाता की मानसिकता में जो बदलाव अनुभव किया जा रहा है उसमें सूझबूझ की परिपक्वता दिखाई दे रही है। ये चुनाव ऐसे मौके पर हो रहे हैं जब राज्य लम्बे दौर की विभिन्न चुनौतियों से जूझने के बाद शांति एवं विकास की राह पर अग्रसर है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बढ़ेगी भारत में बेरोजगारी



अस्सिस्टेंट में ग्राहकों की सेवाओं का बहतर बनाया जा सकेगा। रक्षा के क्षेत्र में भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होना शुश्रू हो गया है। इस तकनीकी के उपयोग से नैतिक और कानूनी चुनौतियां भी बढ़ेंगी। जिन पर विशेष सतर्कता की जरूरत होंगी। एआई तकनीकी के माध्यम से मानव हस्तक्षेप कम होगा। स्वचालित प्रणाली का विकास होगा। ड्रोन और मानव रहित वहां एआई तकनीकी के माध्यम से सैकड़ों संचालित होंगी। एआई तकनीकी का साइबर सुरक्षा में बड़े पैमाने पर उपयोग होगा। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में इस तकनीकी के कारण कई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी इस तकनीकी को जानना जरूरी होगा। एआई तकनीकी के माध्यम से सिस्टम स्वयं निर्णय लेता है। जिसके कारण मानव उपयोग कम होगा। रोबोट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के संचालित होने से बेरोजगारी जैसी

समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। इसका असलॉजिस्टिक और सप्लाई के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होगा। छात्र-छात्राओं को मनवांछित जानकारी विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होगी। परिवहन के क्षेत्र में भी इतकनीकी का उपयोग बड़े पैमाने पर होगा। सरकारी नीतियों, प्रशासन और व्यापारिक संगठनों द्वारा इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। कुमिलाकर एआई तकनीकी भविष्य की सबसे बड़े जरूरत होगी। रोजगार के क्षेत्र में अब एआई तकनीक के जानकारों का बोलवाला होगा। पांच दशक पहलै जैसे टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक था। तीन दशक पहले कंप्यूटर का ज्ञान बहुत आवश्यक होता था। अब कंप्यूटर के साथ-साथ एआई तकनीकी को जान बहुत जरूरी होगा। इसी से रोजगार के अवसर मिलेंगे।

डिजिटलाइजेशन: आसान होती विकसित भारत की राह

2030 तक 7 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ सकती है। एस एंड पी ग्लोबल ने अपनी ग्लोबल क्रेडिट आटलुक 2024 रिपोर्ट-‘न्यू रिस्क, न्यू प्लेबुक’-में कहा है कि भारत की नॉमिनल जीडीपी 2022 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। ‘द इंडियन इकॉनमी: अ रिव्यू’ की रिपोर्ट और एस एंड पी ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक 7 प्रतिशत से अधिक की दर से आगे बढ़ सकती है। ऐसा होता है तो 2030 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 7 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक का हो जाएगा। पुनर्शः ‘द इंडियन इकॉनमी: अ रिव्यू’ रिपोर्ट के अनुसार भी वित वर्ष 2024-25 में लगातार चौथे साल भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रह सकती है, जबकि वित वर्ष 2023-24 में वह 8.2 प्रतिशत रही।

विसिंग ने भारत में एक सब्जी विक्रेता को यूपीआई से भुगतान किया था। भारत डिजिटल भुगतान व दिशा में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। अन्य देशों यूपीआई जैसी कोई भुगतान व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में फेडनाऊ नाम से भुगतान सुविधा है लेकिन इसकी प्रणाली अलग है। भारत सरकार नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा 2016 में विकसित यूपीआई व तकनीक खस्स, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूईई, सऊदी अरब, ओमान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों को उपलब्ध कराई है। वैसे तमाम तरह व चुनावियों के बीच यह कोई अकेला चमकदार पहचान नहीं है।

देश में जनधन खातों की कुल संख्या 52 करोड़ व आंकड़ा पार कर गई है। इनमें 56 प्रतिशत खाता प्रभित्वा 2% से ज्यादा है।

विसिसंग ने भारत में एक सब्जी विक्रेता को यूपीआई से भुगतान किया था। भारत डिजिटल भुगतान विद्या में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। अन्य देशों यूपीआई जैसी कोई भुगतान व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में फेडनाऊ नाम से भुगतान सुविधा है लेकिन इसकी प्रणाली अलग है। भारत सरकार नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा 2016 में विकसित यूपीआई वित्तीय तकनीक खंस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूईई, सऊदी अरब, ओमान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों को उपलब्ध कराई है। वैसे तमाम तरह विचुनौतियों के बीच यह कोई अकेला चमकदार पहल नहीं है।

देश में जनधन खातों की कुल संख्या 52 करोड़ वर्ष औंकड़ा पार कर गई है। इनमें 56 प्रतिशत खाते प्रभित्वा 2में रहे हैं। 2मै 67 प्रतिशत प्रभित्वा 2मै 23%



बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया है। भारत ने तकनीक को न केवल नवाचार के लिए, बल्कि विविध क्षेत्रों में समाधान प्रस्तुत करने के लिए भी अपनाया है, जिससे पिछले कुछ सालों में लोगों के जीवन, परिचालन व्यवस्था, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतंत्र के तकनीकी स्वरूप आदि में बदलाव आया है। भारत में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा में सुधार, पेयजल की आपूर्ति आदि के संदर्भ में तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि की मदद से देश में समावेशी विकास को बल मिल रहा है। डिजिटलाइजेशन ने अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने का काम किया है। आर्थिक, सामाजिक, मानवीय और डिजिटलाइजेशन के मोर्चे पर देश के उम्दा प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत 2047 में विकसित देश बन सकता है।

